

ः : आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा करऔर केन्द्रीय उत्पाद शुल्कः: O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan, रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,



राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142Email: commrappl3-cexamd@nic.in

रजिस्टर्डडाकए.डी. द्वारा :-

DIN-20230564SX000033103F

अपील / फाइनसंख्या/ क Appeal /File No.

मूलआदेशसं / OIO No

दिनांक/ Date

GAPPL/COM/STP/1875/2023

411/D/2022-23

28-02-2023

अपील आदेश संख्या(Order-In-Appeal No.): ख

RAJ-EXCUS-000-APP-121-2023

आदेश का दिनांक / Date of Order:

23.05.2023

जारी करने की तारीख / Date of issue:

23.05.2023

श्री शिव प्रताप सिंह, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri Shiv Pratap Singh, Commissioner (Appeals), Rajkot.

अपर आर्युक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/वस्त् एवंसेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सुजित: / Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham

अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant & Respondent :-

M/s. Core Infrastructure, 50 Uma Society, Sara Road,, Halvad, Dist-Morbi.

इस आदेश (अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है। / Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

सीमा शुल्क , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखि+त जगह की जा सकती है।/ (A)

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर॰ के॰ पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए।/ (i)

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वितीय तल, बहुमाली भवन असार्वा अहमदाबाद- ३८००१६को की जानी चाहिए।/ (ii)

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016in case of appeals other than as mentioned in para-1(a) above

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग , ब्याज की माँग और लगाया गया जुमीता, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक हैं तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक गंजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/ (iii)

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम,1994की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग , ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो कमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भूगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs epenalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

(B)

केन्द्रीय उ

- वित्त अधिनियम,1994की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9 (2) एवं 9 (2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क हारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) &9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal. (i)
- (ii)

- बशर्त यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (स॰ 2) अधिनयम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थान अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।/
For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include:

(i) amount determined under Section 11 D;

(ii) amount determined under Section 11 D;
(iii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

भारत सरकार कोपुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलो में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गतअवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। (C) A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

यदि माल के किसी नुक्सान के मामले में, जहां नुक्सान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुक्सीन के मामले में।/ In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse, to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse (i)

भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)

यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty (iii)

सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी केडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न॰ 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए है।/ Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998. (iv)

उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी (v) हो। भूनिया अत्याव शुल्म जावानवम्, 1944 मा बारा 35 हो। स्वाहण । विकास अर्थ अत्याव शुल्म जावानवम्, 1944 मा बारा 35 हो। स्वाहण । त्रिक्त अर्थ विकास अर्थ हो। त्रिक्त अर्थ विकास अर्थ हो। त्रिक्त अर्थ हो। त्रिक्त के अर्थ हो। त्रिक्त हो। त्

पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए। जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac. (vi)

यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय नयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In cass, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each. (D)

यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended. (E)

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982. (F)

उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in (G)



:: अपील आदेश ::

:: ORDER-IN-APPEAL ::

M/s. Core Infrastructure, 55, Uma Society, Sara Road, Halvad, Tal-Halvad, District- Morbi, Gujarat-363330 (hereinafter referred to as "Appellant") has filed present Appeal against Order-in-Original (OIO) No. 411/D/2022-23 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Assistant Commissioner, Central GST, Division-Morbi-I (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').

- The facts of the case, in brief, are that Income Tax Department provided data/ details of various Income Tax payers, who in their Form 26AS for financial year 2015-16 & 2016-17 declared to have earned income by providing services declared to have earned income by providing services like contractors, I.T. enabled services, Professionals, software development, Commission Agent etc. The Income Tax Department also provided data of Form 26AS showing details of total amount paid/ credited under Section 194C, 194H, 194I & 194J of the Income Tax Act, 1961 in respect of various persons which depicted that such persons had earned income from providing services like contract, commission or brokerage, renting of movable/ immovable property, Technical or Professional service etc. The said data also contained the details of the Appellant who had not obtained Service Tax Registration under the Finance Act, 1994 (hereinafter referred to as 'the Act'). The jurisdictional Assistant Commissioner, vide letters dated 16.07.2020 and subsequent reminders to the Appellant called for the information/ documents. No reply/ response was received from the Appellant and the Service Tax was determined on the basis of data/ details provided by the Income Tax department and culminated into Show Cause Notice and culminated into Show Cause Notice dated 27.04.2021 invoking extended period of 5 years proposing to demand Service Tax of Rs. 8,45,470/-, including all cesses under Section 73(1) of the Finance Act, 1994 (hereinafter referred to as 'the Act') with interest under Section 75 of the Act, and proposing to impose penalty under Section 77(1)(a), 77(2), 77(1)(c) and Section 78 of the Act.
- 3. The adjudicating authority vide the impugned order confirmed Service Tax demand of Rs. 8,45,470/- under Section 73(1) invoking extended period of 5 years along with interest under Section 75 of the Act. The adjudicating authority-imposed penalties of Rs. 10,000/- under Section 77(1)(a), 77(1)(c) and Section 77(2) of the Act. The penalty of Rs. 8,45,470/- was also imposed upon the Appellant under Section 78 of the Act.

Righ

4. The Appellant has preferred the present appeal on 17.04.2022 on various grounds mainly as stated below:

The adjudicating authority has wrongly confirmed demand of Service Tax of Rs. 8,45,470/- under Section 73(1) of the Act, erred in valuation of taxable Services, erred in not allowing the benefit of Notification No. 30/2012 & 33/2012 both dated 20.06.2012, erred in demand of interest u/s 75 of the Act, erred in demanding penalty u/s 77(1)(a), 77(1)(c), 77(2) and 78 of the Act.

- 5. Personal hearing in the matter was held on 04.05.2023 which was attended Shri Nitin Patel, Advocate and Shri Harshad Patel, Consultant, (authorised by appellant), they reiterated the written submission that the appellant provided Work Contract Service with supply of materials and are eligible for abatement applicable, after which the taxable value for both years is below the threshold limit of Rs. 10 Lakhs. They requested to set aside the Order-In-Original.
- 6. Appellant in his written submissions has submitted they are a partnership firm and are engaged in providing work contract service to M/s Paschim Vij Company Limited (hereinafter referred to as PGVCL for sake of brevity). Appellant submitted Audit Report, 26AS, work order of PGVCL & Government authority, purchase bills of material used for work contract along with reconciliation of that work order with entries reflected in Form 26AS.
- 7. I have carefully examined the show cause notice, impugned order, appeal memorandum and written submission of the Appellant. Adjudicating authority has calculated the taxable income as Rs. 57,29,818/-. Service Tax quantified on value of Rs. 57,29,818/- comes to Rs. 8,45,470/-. The issue to be decided in the present appeal is whether amount of Rs. 57,29,818/- reflected as taxable value in impugned order are taxable or otherwise. I find that the Appellant has filed appeal requesting to set aside the impugned order with demand of Service Tax amounting to Rs. 8,45,470/- with Interest and penalties under the Act.
- 8. Regarding amount of Rs. 57,29,818/-, considered as taxable, appellant, vide their written submission, has provided reconciliation statement, copies of work orders, 26AS, etc.

Summary of total relevant period is as under:

Period	Amount (Rs.)			
2014-15	0			
2015-16	28,00,496/-			
2016-17	29,29,322/-			
Total	57,29,818/-			





8.2 Regarding amount of Rs. 57,29,818/-, considered as taxable in impugned order, liability to pay Service Tax by service provider (appellant) as per Rule 2A(ii) of the Service Tax (Determination of Value Rules, 2006), Service Tax shall be payable on 40% of the total amount charged for the works contract. Relevant portion of the said Rule is reproduced as under:

2A. Determination of value of service portion in the execution of a works contract. - Subject to the provisions of section 67, the value of service portion in the execution of a works contract, referred to in clause (h) of section 66E of the Act, shall be determined in the following manner, namely:-

(i)....

- ii) Where the value has not been determined under clause (i), the person liable to pay tax on the service portion involved in the execution of the works contract shall determine the service tax payable in the following manner, namely:-
 - (A) in case of works contracts entered into for execution of original works, service tax shall be payable on forty per cent. of the total amount charged for the works contract;
 - (B) in case of works contract, not covered under sub-clause (A), including works contract entered into for,-
 - (i) maintenance or repair or reconditioning or restoration or servicing of any goods; or
 - (ii) maintenance or repair or completion and finishing services such as glazing or plastering or floor and wall tiling or installation of electrical fittings of immovable property,

8.2.1 Further, as per Sr. No. 09 of the Notification No. 30/2012 dated 20.06.2012 is 50%. Relevant portion of the said Notification is reproduced as under:

Sr. No.	Description of a service [Substituted by the Notification No. 10/2014- ST, dated 11-7-2014 w.e.f. 11-7-2014.]	Percentage of service tax payable by the person providing service	Percentage of service tax payable by any person liable for paying service Tax other than the service provider [Substituted by the Notification No. 7/2015-ST, dated 1-3-2015 w.e.f. 1- 3-2015.]	
9.	in respect of services provided or agreed to be provided in service portion in execution of works contract	50%	50%	

8.2.2 In view of above, detail calculation of tax liability on amount of Rs. 57,29,818/-, considered as taxable in impugned order for the relevant period, is as under:

Period	2014-15	2015-16	2016-17
Particulars			
Taxable- As per Work contract services	0	2800496	2929322
Re-determined value as per Valuation Rules (40% of amount charged)		1120198	1171729
50% of Value as per Reverse Charge Mechanism (RCM)	0	560099	585864
Taxable Value	0	560099	585864

8.2.1 From the above details it is seen that the redetermined value considered as taxable in impugned order in F.Y. 2014-15 is 0/ Nil. Therefore,

Bin

benefit of threshold limit as per Notification No. 33/2012-ST dated 20.06.2012 is available to the taxable amount (redetermined value as per Valuation Rules) for the consecutive year i.e. F.Y. 2015-16 in this case. As such the taxable amount and demand of Service Tax is re-calculated as below:

Period	Taxable value (redetermined as per Valuation Rules) (Rs.)	Threshold limit benefit available (Rs.)	Net Taxable amount (Rs.)	Service amount	Tax demand (Rs.)
2014-15	0	0	. 0		0
2015-16	560099	1000000	0		0
2016-17	585864	1000000	0		0

- 9. Accordingly, as per the worksheet shown above & on the basis of relevant financial records/ documents, the taxable value for the relevant period is determined at 'Nil' and when taxable value is 'Nil' service tax liability is also 'Nil'.
- 10. In view of above discussions, I hold that the Appellant is not liable to pay service tax. I, therefore, set aside the service tax demand on this count. Since, the demand is set aside, recovery of interest under Section 75 and imposition of penalty under Section 77 and 78 are also required to be set aside and I order accordingly.
- 11. In view of the above discussion and findings, I set aside the impugned order and allow the appeal.
- 12. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।
- 12. The appeal filed by the Appellant is disposed off as above.

सत्यापित / Attested

बी. अस. राणा / B. S. RANA अधीक्षक / Superintendent

के. व. एवं सेवा कर अपील्स, राजकीट CGST Appeals, Rajkot (शिव प्रताप सिंह) (Shiv Pratap Singh) आयुक्त (अपील)

Commissioner (Appeals)

By R.P.A.D.

To, M/s. Core Infrastructure, 55, Uma Society, Sara Road, Halvad, District- Morbi, Gujarat-363330. सेवा में, मे॰ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर , 55- उमा सोसाइटी, सरा रोड, हलवद, जिल्ला – मोरबी , गुजरात - 363330 ।

प्रतिलिपि :-

अफी

- 1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) प्रधान आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) अपर/सयुंक्त आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट, को आवश्यक कार्यवाही हेता।
- 4) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मोरबी -1 मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतुं।